

वर्शिव रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024

प्रलिस के लयि:

अंतरराष्ट्रीय शरु संगठन (ILO), बेरोज़गारी, शरु बाज़ार, G20 देश, अनौपचारिक कारु ।

मेन्स के लयि:

वर्शिव रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024 ।

स्रोत: द हद्वि

चरुा में करुयों?

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शरु संगठन (ILO) ने वर्शिव रोज़गार और सामाजिक आउटलुक: रुझान 2024 रिपोर्ट जारी की है, जसिमें बताया गया है की वर्शिव बेरोज़गारी दर वर्ष 2024 में बढ़ने वाली है और बढ़ती असमानताएँ एवं स्थरि उत्पादकता चर्ता का कारण हैं ।

रिपोर्ट के मुखुय तथुय करुा हैं?

- बगिड़ती आरुथक सथतियों के बीच लचीलापन:
 - बगिड़ती आरुथक सथतियों के बावजूद, वर्शुविक शरु बाज़ारों ने बेरोज़गारी दर और नौकरयों के अंतर दर (रोज़गार रहति व्यक्तयों की संखुया जो नौकरी खोजने में रुचि रखते हैं) दोनों में सुधार के साथ आश्चरुयजनक लचीलापन दखुयाया है ।
- वर्शुविक बेरोज़गारी रुझान:
 - वर्ष 2023 में वर्शुविक बेरोज़गारी दर 5.1% थी, जो वर्ष 2022 की तुलना में मामूली सुधार है ।
 - हालाँकि रिपोर्ट में शरु बाज़ार के बगिड़ते परदुशुय का अनुमान लगाया गया है, वर्ष 2024 में अतरिकित 20 लाख शरुमकों के नौकरयों की तलाश करने की उम्मीद है, जसिसे वर्शुविक बेरोज़गारी दर 5.2% तक बढ़ जाएगी ।
- असमान पुनरुप्राप्तः
 - महामारी से उबरना असमान है, नई कडुोरयों और कई संकटों के कारण व्यापक सामाजिक नुयाय की संभावनाएँ कम हो रही हैं ।
 - बेरोज़गारी दर और नौकरयों के अंतर दर दोनों के संदरुभ में, उचुच एवं नडुिन आय वाले देशों के बीच मतभेद बने रहते हैं ।
 - वर्ष 2023 में उचुच आय वाले देशों में बेरोज़गारी अंतराल दर 8.2% था जबकि नडुिन आय वाले देशों में यह 20.5% थी ।
 - इसी प्रकार र्ष 2023 में उचुच आय वाले देशों में बेरोज़गारी दर 4.5% पर बनी रही जबकि कम आय वाले देशों में यह 5.7% थी ।
- आय असमानता में वृद्धः
 - आय असमानता में वृद्धि हुई है तथा अधकिांश G20 देशों में प्रुयोजुय आय में गरिावट आई है ।
 - वास्तविक प्रुयोजुय आय में कडुी को कुल मांग तथा अधकि नरितर आरुथक सुधार के लयि एकनकारात्मक कारक के रूप में देखा जाता है ।
 - प्रुयोजुय आय नवल आय प्रदरुशति करती है । यह करुों के बाद शेष राशिको संदरुभति करती है ।
- कामकाज़ी गरीबी की सथति:
 - वर्ष 2020 के बाद संबद्ध कषेत्तर में तेज़ी से गरिावट के बावजूद अतुयधकि गरीबी में रहने वाले शरुमकों की संखुया (करुय शकतसिमतता के संदरुभ में प्रतु वुयकतुा प्रतुदिनि 2.15 अडेरुकी डॉलर से कम आय) वर्ष 2023 में लगभग 1 डुलियिन बढ़ गई ।
 - मधुयम नरिधनता (PPP के संदरुभ में प्रतु वुयकतुा प्रतुदिनि USD3.65 से कम आय) में रहने वाले शरुमकों की संखुया 2023 में 8.4 डुलियिन बढ़ गई ।
 - कामकाज़ी गरीबी एक चुनौती के रूप में बनी रहने की संभावना है ।
- अनौपचारिक कारुय दरुों की सथति:
 - अनौपचारिक कारुय की दरुों में सथरिता रहने की उम्मीद है जो वर्ष 2024 में वर्शुविक कारुयबल का लगभग 58% है ।
- शरु बाज़ार का असंतुलन:
 - महामारी से पहले शरु बाज़ार में भागीदारी की दर की वापसी वडुिन्न सडुुहों के बीच डुिन्न-डुिन्न रही है ।
 - महिलाओं की भागीदारी में तेज़ी से वापसी हुई है, परंतु लैंगिक अंतर अभी भी बना हुआ है, वर्शुषकर उडुरते और वकिसशील देशों में ।

- युवा बेरोज़गारी दर और **NEET (रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं) श्रेणी उच्च** बनी हुई है, जिससे दीर्घकालिक रोज़गार संभावनाओं के लिये चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं।
- **उत्पादकता में कमी:**
 - महामारी के बाद थोड़े समय के लिये **उत्पादकता** में वृद्धि देखी गई कति **श्रम उत्पादकता पछिले दशक में** देखे गए नमिन स्तर पर लौट आई है।
 - कौशल की कमी और बड़े डिजिटल एकाधिकार के प्रभुत्व सहित बाधाओं के साथ, तकनीकी प्रगति और **बढ़े हुए नविश के बावजूद उत्पादकता वृद्धि धीमी बनी हुई है।**
- **अनश्चिति परदिश्य और संरचनात्मक चिंताएँ:**
 - हाल ही में देखे गए असंतुलन **केवल महामारी का परिणाम मात्र नहीं है बल्कि संरचनात्मक चुनौतियाँ भी** इसका कारण हो सकती हैं। **कार्यबल संबंधी चुनौतियाँ व्यक्तिगत आजीविका और व्यवसाय** दोनों के लिये खतरा पैदा करती हैं।
 - गरिबे जीवन स्तर, **कमजोर उत्पादकता, नरितर मुद्रास्फीति और अधिक असमानता सामाजिक** न्याय तथा सतत् पुनर्प्राप्ति के प्रयासों को कषीण करती है। रपिर्ट इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- **सकारात्मक वास्तविक मज़दूरी:**
 - **भारत और तुर्की में वास्तविक मज़दूरी अन्य G20 देशों की तुलना में "सकारात्मक" है, लेकिन उपलब्ध डेटा 2021 के सापेक्ष 2022 का संदर्भ देता है।** इसका तात्पर्य यह है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत में वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति से आगे निकलने में कामयाब रही है, जिससे वास्तविक मज़दूरी में सुधार में योगदान मिला है।
 - अन्य G20 देशों में वास्तविक मज़दूरी में गिरावट देखी गई; गिरावट **वशेष रूप से ब्राज़ील (6.9%), इटली (5%) और इंडोनेशिया (3.5%) में** देखी गई।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है?

- **परिचय:**
 - इसे वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वरसाय की संधि के हिससे के रूप में बनाया गया था, इस विश्वास को प्रतबिबिति करने के लिये कि सार्वभौमिक तथा स्थायी शांति केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो।
 - यह वर्ष 1946 में **संयुक्त राष्ट्र** की एक विशेष एजेंसी बन गई।
 - यह एक त्रिपक्षीय संगठन है, जो अपनी तरह का एकमात्र संगठन है जो अपने **कार्यकारी निकायों में सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।**
- **सदस्य:**
 - कुल 187 सदस्य देशों के साथ भारत ILO का संस्थापक सदस्य है।
 - 2020 में भारत ने ILO के **शासी निकाय की अध्यक्षता** ग्रहण की।
- **मुख्यालय:**
 - जनिवा, स्विट्ज़रलैंड
- **पुरस्कार:**
 - वर्ष 1969 में, ILO को राष्ट्रों के बीच भाईचारा और शांति में सुधार करने, श्रमिकों के लिये सभ्य कार्य और न्याय प्रदान करने के साथ-साथ अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये **नोबेल शांति पुरस्कार** मिला।

सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 138 और 182 कसिसे संबंधित हैं? (2018)

- बाल श्रम
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिये कृषि प्रथाओं का अनुकूलन
- खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का वनियमन
- कार्यस्थल पर लिंग समानता

उत्तर: (a)